

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 48/प्र0अ0-भवन/जोन-3/शमन/2013-14 दिनांक 27/09/2013

विनियमितीकरण

एह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि एरा भूमि के सम्बन्ध में जिस पर शमन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इसके किसी प्रकार या किसी रखनेवाले निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के पालिकावा अधिकारों पर किसी का कोई अस्स पड़ेगा अर्थात् एह अनुमति किसी के भेदिकता या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री घनश्याम मिश्रा पुत्र स्व0 दुर्गा प्रसाद शुक्ला द्वारा प्लॉट नं0-12 व 13 सिविल स्टेशन, एम0जी0 मार्ग, इलाहाबाद ज० संख्या (3) के अन्तर्गत पालिका विनियमितीकरण मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष नटोदय के अनुमोदनदेश दिनांक 24.09.2013 के द्वारा गिनांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 152 (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/उद्योग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.3 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्त पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर लगाये गये 03 अक्षर दूध को रुदत हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
4. स्थल का उद्योग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
5. स्थानीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदात स्वीकृति मन्नीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. यदि आवेदक द्वारा कोई मरदापूर्ण सूचना छिपयी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
7. गकान निर्माण से बाँदे वाली के सड़क की पट्टी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मरदान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उरुके अकार के कारण ढक गई हो) को धानि रहुँचे तो गुरुत्वाभी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कडा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरदान कराकर पूर्णतः अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
8. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1958 इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूलस 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे तानले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा उट्टा सकता है।
9. यदि भूखण्डों का उप-विभाजन अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इण्डियन नियमानुसार उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
10. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को भवन को नीँट तक तथा छत तक बन जाने एवं उसको पूर्ण हो जाने की सूचना गकान अबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में भवन निर्मित हुआ है।
11. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द कराई जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही अरम्भ की जायेगी।

Ramesh
Ramesh
27/9/13

(मुडाकेरा शर्मा)
संयुक्त सचिव/प्र0अ0-भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद

